**भारत सरकार**
**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**
**19.03.2025 के**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3060 का उत्तर**

**नेटवर्क दक्षता के लिए समर्पित माल गलियारा**

**3060. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:**
**श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:**
**श्री बैन्नी बेहनन:**
**एडवोकेट अदूर प्रकाश:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या सरकार का नये समर्पित माल गलियारों का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ख) समर्पित माल गलियारों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनके पूरा होने की अपेक्षित समय सीमा क्या है;**

**(ग) सरकार माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने और समग्र नेटवर्क दक्षता में सुधार करने के लिए समर्पित माल गलियारों (डीएफसी) का किस प्रकार उपयोग कर रही है;**

**(घ) इन गलियारों का माल परिवहन दक्षता और रसद लागत पर क्या प्रभाव होगा;**

**(ङ) क्या समर्पित माल ढुलाई गलियारे के माध्यम से केरल सहित दक्षिणी राज्यों को जोड़ने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(च) रेलवे की आधारभूत संरचना, चल स्टॉक और सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;**

**(छ) वित्त वर्ष 2025 में रेलवे अवसंरचना विस्तार के लिए कितना वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है;**

**(ज) गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल किस प्रकार कार्गो क्षेत्र में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी बढ़ाने में योगदान करते हैं; और**

(झ) विगत पांच वर्षों के दौरान माल लदान और राजस्व से संबंधित प्रमुख आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल मंत्रालय ने दो समर्पित माल यातायात गलियारों (डीएफसी) अर्थात लुधियाना से सोननगर (1337 किमी) तक पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारा (ईडीएफसी) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (जेएनपीटी) से दादरी (1506 किमी) तक पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) के निर्माण का कार्य शुरु किया है। कुल 2843 कि.मी. में से 2741 मार्ग किलोमीटर (96.4%) को कमीशन किया गया है और परिचालित किया जा रहा है। शेष खंड के कार्य शुरू किए गए हैं।

रेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित तीन (03) नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य शुरु किया गया है:-

(i) पूर्व तट गलियारा: खड़गपुर से विजयवाड़ा

(ii) पूर्व-पश्चिम गलियारा:
(क) पालघर-भुसावल-नागपुर-खड़गपुर-दानकुनी
(ख) राजखरसवां - कालीपहाड़ी - अंडाल

(iii) उत्तर-दक्षिण उप-गलियारा: विजयवाड़ा-नागपुर-इटारसी

उपरोक्त तीन गलियारों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

उपरोक्त तीन डीएफसी में से किसी को भी अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। डीएफसी परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी प्रधान हैं और किसी भी डीएफसी परियोजना की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय और आर्थिक क्षमता, यातायात की मांग और निधियों एवं वित्तीय विकल्पों की उपलब्धता आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

समर्पित माल गलियारा (डीएफसी) परियोजना से पारवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे डबल स्टैक कंटेनर (डीएससी) गाड़ियों, उच्चतर धुरा भार गाड़ियों की आवाजाही में वृद्धि होगी, पश्चिमी पत्तनों द्वारा भीतरी

उत्तरी क्षेत्रों तक तीव्र पहुंच और उद्योगों के साथ नए टर्मिनलों/संपर्क सूत्रों के विकास को संभव बनाएगी। पूर्वी डीएफसी से पूर्वी भारत से खनिज यातायात की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इन विकास कार्यों से लॉजिस्टिक लागत को कम करने में सक्षमता प्राप्त होगी।

समर्पित माल गलियारों द्वारा माल यातायात को पूर्वी समर्पित माल गलियारे और पश्चिमी समर्पित माल गलियारे की ओर मोड़कर पारंपरिक नेटवर्क पर अतिरिक्त मार्ग सृजित करने में योगदान दिया है। समर्पित माल गलियारों पर यातायात वर्ष 2023-24 में औसतन 247 रेलगाड़ियों से 2024-25 (फरवरी 2025 तक) में औसतन 352 गाड़ियों तक बढ़ गया है। फरवरी 2025 में, औसतन 371 गाड़ियां परिचालित की गई। इसके परिणामस्वरूप, रेलवे को अपने नेटवर्क पर बेहतर समयपालन के साथ अतिरिक्त माल और यात्री सेवाओं के परिचालन में सक्षमता मिली है। रेलगाड़ी सेवाओं, माल और यात्री सेवाओं दोनों में वृद्धि के कारण, भारतीय रेल की गाड़ी सेवाओं से आमदनी में वृद्धि हुई है।

(च): परिचालनिक आवश्यकता, तकनीकी संभाव्यता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक आवश्यकता आधारित है और एक सतत् प्रक्रिया है।

चल स्टॉक और सिगनल प्रणाली सहित रेल अवसंरचना के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कई कार्य शुरू किए गए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

1. वर्ष 2017-18 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ₹1 लाख करोड़ की राशि के साथ महत्वपूर्ण संरक्षा परिसंपत्तियों के बदलाव/नवीकरण/उन्नयन के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष शुरू किया गया था। सरकार द्वारा ₹45,000 करोड़ की सकल बजटीय सहायता के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की वैधता को 2021-22 से आगे अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। संशोधित अनुमान 2024-25 में 12800 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है।
2. दिनांक 28.02.2025 तक 6623 रेलवे स्टेशनों पर पॉइंटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन के साथ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली मुहैया कराई गई हैं।
3. रेल फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 28.02.2025 तक 11,089 रेल फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।
4. 28.02.2025 तक 6126 ब्लॉक खंडों पर ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर (बीपीएसी) प्रणाली मुहैया कराई गई है।

5. 28.02.2025 तक 5221 मार्ग किलोमीटर पर स्वचालित ब्लॉक सिगनल प्रणाली (एबीएस) मुहैया कराई गई है।
6. भारतीय रेल ने स्वचालित गाड़ी सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली के रूप में उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणाली 'कवच' के कार्यान्वयन शुरु किया है। कवच स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित गाड़ी सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है जिसके लिए उच्चतम स्तर के संरक्षा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में भी अपनाया गया है।
7. घटना पश्चात विश्लेषण के लिए रेल इंजनों में क्रू वीडियो और वॉयस रिकार्डिंग प्रणाली (सीवीवीआरएस) मुहैया कराई गई है।
8. रेलगाड़ियों में प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलन के लिए एलएचबी सवारी डिब्बों में बिजली की आपूर्ति के लिए पैसेंजर इंजनों में हेड ऑन जनरेशन (एचओजी) योजना कार्यान्वित की गई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन, ध्वनि का स्तर और जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी आई है।
9. रेलवे ने माल यातायात परिचालन के लिए नई प्रौद्योगिकी वाले 12000 एचपी के बिजली इंजन और 9000 एचपी के बिजली इंजन प्राप्त करने की दीर्घकालिक योजना बनाई है। नई प्रौद्योगिकी आधारित 9000 उच्च गति अश्व शक्ति विद्युत मालगाड़ी रेलइंजनों के विनिर्माण के लिए दाहोद में एक विनिर्माण यूनिट, जिसमें आधुनिक विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाएं हैं, को मंजूरी दी गई है।
10. थ्रुपुट बढ़ाने की दृष्टि से, आरडीएसओ ने आधुनिक मालडिब्बों (मॉडर्न ओपन मालडिब्बे और मॉडर्न ब्रेक वैन) के लिए तकनीकी निर्दिष्टियां जारी की हैं। हाल ही में, बहुउद्देश्यीय और उच्च वहन क्षमता वाले मालडिब्बों को आरडीएसओ द्वारा डिजाइन किया गया है। ये मालडिब्बे चल परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग में मदद करेंगे और प्रति रेक थ्रुपुट में वृद्धि करेंगे।
11. इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) रेलगाड़ियों, मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) रेलगाड़ियों, कोलकाता मेट्रो रेकों और इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी सेटों में रिजेनरेटिव ब्रेकन प्रणाली के साथ आईजीबीटी आधारित 3-फेज प्रणोदन प्रणाली की शुरुआत।
12. एलएचबी सवारीडिब्बों के अनुरक्षण और जांच के लिए धुलाई/सिक लाइनों पर 750 वोल्ट की बाहरी बिजली आपूर्ति का प्रावधान जिससे डीजल की भारी बचत होगी।
13. रेलपथ संरचना का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के संबंध में उठाए गए कदमों में 1660 स्लीपर के साथ पूर्व स्ट्रेस्ड प्रबलित कंक्रीट (पीएससी) स्लीपरों पर 60 किग्रा/90 चरम तन्य सामर्थ्य पटरी से युक्त रेलपथ संरचना बिछाना, लंबी रेल बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग का उपयोग कम करना और पटरियों के लिए

बेहतर वेल्डिंग तकनीक अर्थात फ्लैश बट वेल्डिंग को अपनाना, थिक वेब स्विच और वेल्डेबल कास्ट मैंगनीज स्टील (डब्ल्यूसीएमएस) क्रॉसिंग का उपयोग, बेहतर फिटिंग का उपयोग करना, रेलपथ मशीनों की सहायता से रेलपथ का अनुरक्षण करना पटरियों की अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन जांच आदि शामिल है।

14. बुजुर्गों, बीमार, अलग-अलग दिव्यांग यात्रियों की सुलभ आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों तक आसान पहुंच और आवागमन में सरलता के लिए, स्टेशनों की तुलनात्मक प्राथमिकता, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर लिफ्ट और एस्केलेटर प्रदान किए जाते हैं।

(छ): भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन निम्नानुसार दिया गया है:

| अवधि | औसत परिव्यय | वर्ष 2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि |
|---|---|---|
| 2009-14 | 11,527 करोड़ रु. प्रतिवर्ष | - |
| 2024-25 | 68,634 करोड़ रु. | लगभग 6 गुना |

(ज): भारतीय रेल में माल यातायात वहन क्षमता बढ़ाने के लिए, दिनांक 15.12.2021 को 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य रेल कार्गो को संभालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनलों के विकास में उद्योग से निवेश बढ़ाना है। जीसीटी मशीनीकृत लदान/उतराई की सुविधा से भी युक्त हैं, जिससे व्यापार के लिए पारगमन समय और लागत को कम करने में योगदान मिलेगा। अब तक 97 जीसीटी कमीशन किए गए हैं, जो रेलवे के लिए अतिरिक्त माल यातायात को सक्षम बनाते हैं। गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों के लिए 277 प्रस्तावों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (टीपीए) पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(झ): पिछले पांच वर्षों के दौरान माल लदान और राजस्व के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

| वर्ष | माल लदान (मिलियन टन में) | माल से राजस्व आमदनी (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 2019-2024 | 6952.3 | 7,02,372.29 |

******